gone. There will be no actual accountability and the nation will be losing money on this. What exactly is the way? How can you stop this? How can you recover this money?

SHRI DAYANIDHI MARAN: I would like to answer to the Member through you, Sir. The question is related to illegal exchanges which are run in toilets, in small rooms, etc. We can only take actions on that. If the Member has information which he can share with us or with the Department...(*Interruptions*)...Please wait. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I have this information before me that Rs.45 lakh have been lost. How are you going to recover it? This is the question. ...(*Interruptions*) ... Rupees 45 lakhs have been lost. How are you going to recover it? ...*(Interruptions)* ... Please tell me.

MR. CHAIRMAN: Next question, Shri Sanjay Nirupam.

Incentives for workers in ARIs

*134. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of AGRO AND RURAL INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have given/planned any incentives for the workers in agro and rural industries;

(b) whether Government have released the funds for the ruining industries to activate for the benefit of the workers who have lost their jobs; and

(c) if so, the details regarding the incentives and funds released for and the list of action plan taken about?

THE MINISTER OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) to (c) A Statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) Under the Rural Employment Generation Programme (REGP) of the Government, being implemented through the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), entrepreneurs can establish agro and rural

industries, including village industries, by availing of margin money assistance from the KVIC and loans from any public sector scheduled commercial bank, for projects with a maximum cost of Rs. 25 lakh. The margin money assistance is given as detailed in the table below.

Margin Money Assistance under REGP

Sl. No.	Category of beneficiary	Project cost	Margin mone assistance
1.	General	Upto Rs. 10 lakh	25 per cent of project cost
2.	SC/ST/Women/Ex-serviceman/NE Region/ Hill areas	Upto 10 lakh	30 per cent of project cost
3.	General	Rs. 10 lakh and Upto Rs. 25 lakh	Rs.2.5 lakh+10 per cent of balance project cost.
4.	SC/ST/Women/Ex-service man/NE Region/Hill areas	Rs. 10 lakh and upto Rs. 25 lakh	Rs. 3 lakh + 10 per cent of balance project cost.

NOTE: SC/ST—Scheduled Caste/Scheduled Tribe; NE—North Eastern

Under the REGP, 1,86,252 projects have been financed generating 22.75 lakh additional employment upto 31st March, 2004 since its inception and a sum of Rs. 1079.47 crore has been released as margin money assistance to entrepreneurs.

Under the Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY) of the Government, being implemented through the District Industries Centres (DICs) of the States/Union Territories (UTs) and the banks, loans are provided to the educated unemployed to set up self-employment ventures. Under the PMRY, the Central Government allocates funds for subsidy, entrepreneurial development training (EDT),contingencies, etc., based on the targets of generation of employment opportunities assigned to each State/UT. The Central funds for subsidy are routed through the Reserve Bank of India

(RBI) which, in turn, passes them on to the implementing banks for crediting the amounts to the loan accounts of each beneficiary. Under this Yojana, projects with investment upto Rs. 1 lakh in the business sector and upto Rs. 2 lakh in other sectors are eligible for assistance. The subsidy amount is 15 per cent of project cost and subject to a ceiling of Rs. 7,500/-.Eligible persons can join together in a partnership to get assistance for projects with investment upto Rs. 10 lakh. The margin money contribution of the beneficiary varies from 5 per cent to 16.25 per cent to 16.25 per cent of the project cost, so as to make sum of the Government subsidy and beneficiary's own contribution to margin money equal to 20 per cent of the project cost. Since the inception of the PMRY, 29.98 lakh employment opportunities are estimated to have been created and a sum of Rs. 1382 crore has been released as subsidy to the unemployed beneficiaries till 31 March 2004.

The Central Government provides assistance under the REGP and PMRY for setting up new units/self-employment ventures. Existing units/ self-employment ventures, which were set up with credit from banks and margin money assistance from the Government but have now become sick, are eligible for the rehabilitation assistance available to sick units in the small scale industries (SSI) sector, as per the guidelines of the Reserve Bank of India (RBI). These measures include, *inter-alia*:

(i) Waiver of penal interest on cash credit and term loan from the year the unit started making cash losses.

(ii) Unpaid interest on cash credit and term loan should be segregated from the total liability and the former amount treated as a separate interest-free loan.

(iii) Reduced rate of interest (reduction of upto 3 per cent for tiny units and of upto 2 per cent for SSI units) should be charged on unpaid term loans.

(iv)Additional working capital loan should be given at a rate of interest not exceeding the prime lending rate.

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न को मंत्री महोदय ने समझा ही नहीं है। आप सदन शुरू होने से पहले स्वयं

प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर भी देखते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्कर्स को क्या इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जो इंडस्ट्रीज़ बर्बाद हो चुकी हैं, उनके वर्कर्स को फिर से जॉब दिलाने के लिए क्या इंतजाम हो रहा है? मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की दो योजनाओं को विस्तार से यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। एक योजना है–रूरल इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम और दूसरी योजना है–प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। हमारे पास मंत्रालय की जो एनुअल रिपोर्ट आती है, इनके समाचार विस्तार से उसमें उपलब्ध होते हैं। इसलिए जो प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब ही गलत है। मंत्री महोदय सबसे पहले यह बताएं कि वे प्रश्न समझ पाए या नहीं समझ पाए, आपके ऑफिसर लोग आपको बता पाए या नहीं बता पाए, तब तो आगे कुछ सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का जुगाड़ लगाया जाए।

श्री सभापति: आप तो पहले ही सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, दो रोजगार योजनाओं के संदर्भ में उन्होंने जो जानकारी दी है, उन्हीं पर मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने बताया है कि–"Under the REGP, 1,86,252 projects have been financed generating 22.75 lakh additional employment upto 31st March, 2004 since its inception..." यह तो REGP का है, और प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के संदर्भ में इन्होंने बताया है कि लगभग 29 लाख इम्प्लॉयमेंट अपार्चुनिटीज़ क्रियेट की गई हैं और since its inception, लगभग 1,382 करोड़ रुपए फाइनेंस किए गए हैं। अब यह सबसिडी नहीं है, यह बिजनेस है। इन दोनों योजनाओं के तहत बिजनेस करने के लिए रूरल अनइम्प्लायड एजुकेटेड लोगों को हमने पैसे दिए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका हिसाब-किताब आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैसे दिए गए थे, उनका हुआ क्या? मुझे यह जानना है कि दोनों योजनाओं के तहत जो भी हजार-हजार करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मारजिन मनी के तौर पर अपना असिस्टेंस दिया, उसका रिजल्ट क्या निकला? कितनी इन्डस्ट्रीज चल रही हैं, कितनी इन्डस्ट्रीज बन्द हो गई हैं? बन्द हो गईं तो क्यों हो गईं? इसकी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करें।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। इनको जवाब देने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति जी, सम्मानित विद्वान सदस्य...

श्री सभापति: पहले से ही भूमिका क्यों बना रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद: बना इसलिए रहा हूँ कि उन्होंने मंत्री जी के ऊपर कहा कि मंत्री जी ने उस प्रश्न को नहीं समझा और मैं माननीय सदस्य महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्रालय में दो विषय हैं–एक एस.एस.आई. का, लघु उद्योग इन्डस्ट्रीज हैं, दूसरे कृषि पर आधारित उद्योग हैं।

माननीय सदस्य महोदय को सीधे जो प्रश्न पूछना चाहिए था, मैं उनसे फिर से कहना चाहूँगा कि जब वे उचित समझें तो फिर से यह प्रश्न करें, जिस तरीके से प्रश्न करना चाहिए, तो मैं इनका जवाब पूरे रूप से दूँगा। . ..(**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्रश्न कैसे पूछा जाए, यह बताएँ ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: सेकंड सप्लीमेंटरी पूछ लीजिए।

श्री संजय निरुपम: सभापति जी मैंने अपने माननीय वरिष्ठ, विद्वान मंत्री महोदय से सीधे-सीधे शब्दों में सवाल पूछा ...(**व्यवधान**)। सभापति जी, मैंने अपने वरिष्ठतम मंत्री महोदय से सीधे-सीधे शब्दों में सवाल पूछा कि एक-एक हजार करोड़ रुपए दो रोजगार योजनाओं में अब तक केन्द्र सरकार की तरफ से खर्च किया जा चुका है, उस पैसे का हिसाब-किताब क्या है और जो उद्योग-धंधे शुरु किए गए, उन उद्योग-धंधों की ताजा स्थिति क्या है? मुझे मालूम है कि साहब, सैकंड सप्लीमेंटरी नहीं पूछने देंगे, इसलिए ...(**व्यवधान**) नहीं तो सेकंड सप्लीमेंटरी करने का वचन दें तो मैं बैठता हूँ।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, ये क्वेश्चन समझ गए। दूसरी सप्लीमेंटरी रहने दीजिए। ...(**व्यवधान**) यह आप वाला क्वैश्चन जो....आपने जो क्वैश्चन किया, वे समझ गए, जवाब दे देंगे।

संजय निरुपम: मुझे दूसरी सप्लीमेंटरी करने की कृपया अनुमति दें।

श्री सभापति: नहीं, इससे फिर कंफ्यूज़न हो जाएगा।

श्री संजय निरुपम: अभी तो पहली सप्लीमेंटरी चल रही है। जी साहब, मंत्री जी बताएँ।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि मैंने पहले आपके माध्यम से उनसे आग्रह किया कि भारत सरकार में, हमारी सरकार में, केन्द्र सरकार में दो प्रकार के जो यूनिट या उद्योग-धंधे लगते हैं, एक लघु उद्योग जिसे हम कहते हैं, स्माल स्केल इन्डस्ट्री..

श्री सभापति: यह तो वही जवाब दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद: जवाब तो दे रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने एक आक्षेप आते-आते लगाया कि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को समझा नहीं। मैं फिर से आग्रह करुँगा आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य महोदय से आग्रह करुँगा कि हमारे यहाँ उन्होंने पूछा है प्रश्न में, मूल प्रश्न में मैंने बिल्कुल साफ कहा है कि केन्द्र सरकार आर.ई.जी.पी. तथा पी.एम.आर.वाई. के तहत नई यूनिटों और स्व-रोजगार उपक्रमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है। मौजूदा यूनिटें स्व-रोजगार उपलब्ध ...(**व्यवधान**) माननीय सभापति जी, मैं ...(**व्यवधान**)

श्री रुद्रनारायण पणी: सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाए।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, एक सर्वे जो हुआ, उस सर्वे के आधार पर आर.ई.जी.पी. में 70 प्रतिशत उद्योग ठीक से चल रहे हैं और 15 प्रतिशत सिक यूनिट हो गए हैं और 15 प्रतिशत यूनिट बन्द पड़े हुए हैं। इस प्रकार से इसमें पैकेज देने का जो यूनिट का सवाल है, सर, यह इकाई होती है, यूनिट होता है, इसमें मजदूर का सवाल नहीं होता है इसलिए जो हमारी इकाई, मैं पुन: दोहरा देना चाहता हूँ कि सर्वेक्षण के आधार पर हमारे पास जो आँकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर माननीय सदस्य महोदय को मैंने बताया और फिर से मैं उनसे आग्रह करूँगा कि भविष्य में सीधे प्रश्न हमसे करें तो मैं इनका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दे दूँगा माननीय विद्वान सदस्य को।

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग-धंधे ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। महोदय, एस॰एस॰आई॰ और अन्य वर्ग की इन योजनाओं के अंतर्गत जो छोटे-छोटे उद्योग शुरू किए जा रहे हैं, उन के अच्छे ढंग से न चल पाने का कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अपने लोन पर लगभग 10 से 12 परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को मिलने वाले लोन पर इंटरेस्ट 8 से 9 परसेंट होता है इसलिए एक विचार बार-बार आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम छोटे-छोटे गरीब बेरोजगारों को बैंकों की तरफ से जो लोन देते हैं, उन का इंटरेस्ट रेट भी 7 से 8 परसेंट किया जाना चाहिए। महोदय, हमारे मंत्री जी जोकि ग्रामीण उद्योग और गरीब लोगों के धंधों के इंचार्ज मंत्री हैं, उन से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? क्या आप ऐसा कोई प्रस्ताव प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं ताकि ग्रामीण औद्योगीकरण का वातावरण और दुरुस्त हो सके? ...(**व्यवधान**)... महोदय, अगर माननीय प्रधान मंत्री जी इस सवाल का जवाब दे दें तो सचमुच आनंद आ जाएगा और ग्रामीण बेरोजगारों को एक मैसेज जाएगा कि प्रधान मंत्री जी के मन में क्या है।

श्री सभापति: आप बोलते जायेंगें तो क्या समस्या का समाधान आ जाएगा? आप विद्वान मंत्री जी का जवाब तो सुनिए।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार का यह संकल्प है कि ग्रामीण अंचल में हम लोगों को अधिक-से-अधिक रोजगार दें और इस के तहत जहां बैंकों से ऋण देने का सवाल है, हम प्राइम लेंडिंग रेट के तहत कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में वित्त मंत्री महोदय से भी चर्चा हुई है और रिजर्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य धैर्य रखिए और सुनिए। तो हमारी सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से और बैंकों के सामूहिक उत्तरदायित्व की तरफ से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, उन के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार का जो संयुक्त कार्यक्रम है उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक-से-अधिक पूरा करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री संजय निरुपम: महोदय, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों के लिए बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं? ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद: महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: आप ठहरिए। मैं मंत्री महोदय और माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर विचार के लिए अगर आप "हाफ एन ऑवर" डिस्कसन की मांग करें तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं।...(व्यवधान)... अगला प्रश्न प्रो॰ एम॰एम॰ अग्रवाल।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि हम इस बारे में अधिक-से-अधिक कोशिश कर रहे हैं कि वहां ब्याज दर कम की जाए।

श्री सभापति: मैंने आप दोनों को कहा कि आप अच्छी तरह से विचार कर के आ जाएं।

प्रश्न संख्या 135.

Upgradation of Branch Post Offices

*135. PROF. M.M. AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to upgrade branch post offices functioning at present in the different parts of the country;

(b) if so, the details thereof, district-wise/category-wise; and

(c) the steps being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Upgradation of branch post offices

There are 49 proposals under consideration for upgrading Extra Departmental Branch Post Offices and Extra Departmental Sub Post Offices to Departmental Sub Post Offices. District-wise and category-wise details of these proposals are given in enclosed Statement-I (*See below*).

Proposals which are found to be justified as per prescribed norms, are upgraded to Department Sub Post Offices. The norms for upgradation of